ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 14, Issue 11, Nov 2024 Impact Factor 8.059 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

अस्तित्व की तलाश में फलस्तीन

डॉ0 अजय कुमार पाण्डेय, एसो0प्रो0
रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग
श्री मु0म0टाउन पी0जी0 कॉलेज, बलिया

समबुद्धिर्विशिष्यते ! अर्थात जो सब में भाववाला है, वह अति श्रेष्ठ है की सम्भाव्यता से विरक्त मानव या राष्ट्र व्यक्तिगत उन्नति के चकाचौंध अन्धानुकरण में संलिप्त है। इस संलिप्तता में यदि एक मात्र और कोई न हो तो आधिपत्य व प्रभावशीलता किस पर और क्यों? स्वयं में अस्तित्व विहिन है। विगत एक दशक से वैश्विक परिदृश्य की विषमता यथा रूस–युक्रेन, इजराइल–हमास–फलीस्तीन, कोविड–19 की भयावहता ने अस्थिरता की ओर चक्रमणित कर तनाव में वृद्धि कर दिया है। इजराइल–फलस्तीन की तस्वीर पश्चात विश्व राष्ट्र को इस प्रश्न का जबाव/उत्तर भी देना होगा कि संघर्ष–विराम के पश्चात आखिर क्या? बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री इजराइल ने जब अपने सैनिकों के मध्य गाजा पहुंचे तो उन्होंने अपने लक्ष्यों को स्पष्ट किया जो इस प्रकार हैः–

1– जब तब जीत नहीं मिल जाती तब तक संघर्ष/युद्ध को अनवरत जारी रखेंगे।

2– हमास को खत्म अर्थात नेस्तनाबूत करना।

3– अपने सभी बंधक साथियों को वापस ले जाना।

4– यह सुनिश्चित करना की गाजा पुनः इजराइल के लिए खतरा न बने।

5– सीमावर्ती राष्ट्र को यह चेतावनी देना कि उससे युद्ध लड़ने का परिणाम क्या होगा?

एक रिपोर्ट के अनुसार–इजराइल की योजना गाजापट्टी के 20 लाख से अधिक फलस्तीनियों को कुछ वर्गमील क्षेत्र में सीमित कर भविष्यगत खतरे को खत्म कर देना था। गाजा–पट्टी लगभग 140 वर्गमील में विस्तारित हमास के नियंत्रण में है।[1] यदि दुनिया शान्तिमय स्थिति में फलस्तीनियों को अपने ही घर, जमीन, सम्पत्ति से दबावगत भगाने अथवा बेदखल करने का उपक्रम देखती रही तो भविष्य में अन्य राष्ट्र का क्या होगा? क्योंकि विश्व संगठन संयुक्त राष्ट्र या उसकी सुरक्षा परिषद पूर्णतः मौन उसकी असफलता का द्योतक है। अतः फलीस्तीन ने आत्मबल का परिचय दिया क्योंकि आत्मबल ही विषम से विषम परिस्थितियों का सर्वोत्तम बल है। फलस्तीन का आत्मबल निम्नानुसार हैः–

- 07 अक्टूबर 2023 को इजराइली प्रतिबंधियों से क्रूरता के साथ प्रदर्शन।
- कभी किसी स्थिति में गम्भीर प्रतिक्रिया की प्रदर्शिता।
- इजराइल एवं पश्चिमी दुनिया जनसंख्या में अधिक होने के कारण फलस्तीन को सुरक्षित, सम्मानजनक मातृभूमि की आवश्यकता की सिद्दत।

फलस्तीनी अधिकारों के लिए यूरोप एवं अमेरिका की सड़कों पर बड़ी संख्या में विविध धर्मी लोगों का प्रदर्शन से स्वीकारना होगा कि फलस्तीन की स्वतंत्र राष्ट्र के लिए इजराइल से लड़ाई जमीरी था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियों वक्तव्य में चिंतापरक स्थिति में परिव्यक्त किया था कि – इतने सारे लोग मर रहे है, इजराइली व यहूदी लोगों के

प्रति

फलस्तीनी नफरत जैसी कोई नफरत नहीं है और शायद इसके समाधान का दूसरा तरीका भी है।[2] विचारको की प्रतिक्रिया में एक माह पूर्व ही ट्रंप इस प्रकार के वक्तव्य दे सकते थे लेकिन क्यों नहीं दिया ? परिस्थितियों की प्रतिकूलता में धैर्यता ही श्रेष्ठ है। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री भारत सरकार ने इजराइल के अपने रक्षा के अधिकार को उचित माना किन्तु विदेश मंत्रालय के माध्यम से सुरक्षित व मान्यता प्राप्त सीमा के अन्दर सम्प्रभु स्वतंत्र व व्यवहार्य फलस्तीन के लिए इजराइल के साथ शान्ति से सीधी बातचीत का आह्वान किया गया। समकालीन परिस्थिति में ऐसे अनेक भारतीय नागरिक है जो एक ऐसे विश्व की कल्पना करते है, जिसके नक्शे (मानचित्र) में पाकिस्तान का कोई अस्तित्व न हो। पाकिस्तान विश्व मानचित्र में बेशक विद्यमान हो किन्तु कठोर सत्य है कि वह अस्तित्व विहिन जर्जर पूर्णतः पंगु अपनी गलत कूटनीतियों के कारण हो गया है। पाकिस्तान के पूर्व वजीरे आला इमरान खान की चेहरे से स्पष्टतः काली करतूते बयां करते है। कंठ से आवाज नहीं नजरों में शौर्य हीनता। इजराइल–फलस्तीन की सच्चाई को भारत–पाकिस्तान संदर्भ में तुलना एवं विश्लेषण से सच्चाई स्वतः स्पष्ट हो जाएगी। दूरस्थ सीमा में आसीन किसी भी राष्ट्र की बफादारी, तरफदारी व गद्दारी करने से इंकार नहीं किया जा सकता है। आज कोई भी ऐसी शक्ति अथवा विश्व संगठन नहीं है जो किसी भी राष्ट्र को सुरक्षा की गारन्टी दे सके।

गाजा की प्रशासनिक व्यवस्था में इजराइल, हमास को किसी भी प्रकार की भूमिका देने को तैयार नहीं है। मिस्र के विचार में महमूद अब्बास का फतहगुट व हमास संयुक्त रूप से काम करें। कतर–मिस्र के मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। हमास, यूनिटी सरकार की अवधारणा पर विचार के लिए तैयार है। बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से स्पष्ट कर चुके है कि सुधरी एवं पुर्नगठित फलस्तीनी अथॉरिटी को गाजा की सत्ता सौंपी जा सकती है पर इस तथ्य की गारन्टी कौन देगा कि वहीं चरमपंथी विचारों को पुनः पैर जमाने का मौका नहीं मिलेगा।[3] पश्चिमी एशिया में इजराइल हमास युद्ध/संघर्ष ने राष्ट्रों की रणनीति, विदेश नीति में तीव्रता से परिवर्तन एवं आर्थिक व्यवस्था को अस्थिर बना दिया। फलस्तीन समस्या के समाधान में हमारे महान राष्ट्र भारत का गहरा जुड़ाव है। पश्चिम एशिया के साथ हमारे राष्ट्र के मात्र आर्थिक सम्बन्ध ही नहीं, अपितु सामाजिक व सांस्कृतिक सम्बन्ध भी निहित है। यद्यपि फलस्तीन एक राष्ट्र के रूप में स्वयं खड़ा नहीं है। मिस्र, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, ईरान, भारत के सहयोग पर राष्ट्र के रूप में दर्श है। वर्ष 1993 ई0 में 'ओस्लो समझौते' (शान्ति का रोडमैप) व सम्मेलन के पश्चात वर्ष 1994 ई० फलस्तीन राष्ट्रीय प्राधिकरण मूलतः 5 वर्ष के लिए अंतरिम व्यवस्था से युक्त पूर्ण राष्ट्र की संज्ञा दी जानी थी; सम्भवतः अथवा मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। वर्ष 2002 ई0 में फलस्तीन अथॉरिटी (PA) की एक अंतरिम संविधान एवं वर्ष 2005 ई० में कुछ संसोधन कर वर्तमान तक संचालित किए जा रहे है। फलस्तीन अथॉरिटी की राजधानी जार्डन नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित रामल्ला में है। यद्यपि ओस्लो समझौते से पूर्व इसे मुख्यधारा से जोड़ने की प्रक्रिया के साथ अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र में गैर सदस्य पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में स्वीकृत था। 07 अक्टूबर 2023 में गाजा में युद्ध प्रारम्भ से पूर्व जार्डन नदी का पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र फतह के नियंत्रण एवं गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा (अधिकार) था। फलस्तीनी अथॉरिटी का प्रभाव आज भी पश्चिमी किनारे तक सीमित, हमास के प्रभाव में हैं। महमूद अब्बास राष्ट्रपति फलस्तीन जिनके पास यासर अरफात की विरासत है। हमास–इजराइल आलोक है। मध्यमार्गी तबका या तो है या नहीं, और है तो निश्चित कमजोर है जिससे फलस्तीनी अथॉरिटी में व्याप्त भ्रष्टाचार, हमास नियंत्रित गाजापट्टी में जीवन अराजक है जिसका मुख्य कारण फलस्तीन को पूर्व राष्ट्र का दर्जा न मिलना है। लगभग दो दशक पूर्व इलिनोइस विश्वविद्यालय में एक अतिथि भारतीय राजनीतिक विचारक अपने एक व्याख्यॉन में स्पष्ट किया था कि– भारत–पाकिस्तान की तुलना में

इजराइल–फलस्तीन विवाद को सुलझाना अपेक्षाकृत सहज है इसके लिए हमें दोनों में समानताएं देखनी चाहिए। अनेक फलस्तीनी नागरिक नाराज इजराइल का गठन उसकी जमीन पर बस्तियों के माध्यम से क्यों किया गया जो सदियों से फलस्तीनियों की थी जबकि इजराइल अपने पड़ोस व सीमा में फलस्तीनियों के अस्तित्व से घृणित है जो विवाद, संघर्ष व युद्ध का स्वरूप धारण करता है जिसमें द्विपक्षीय भीषण क्षति के साथ–साथ बहुपक्षीय प्रभाव पड़ता है। सदियों से इस प्रकार की कृ तियों में उलझने से हानि के अतिरिक्त लाभ की सम्भाव्यता नही होती है। समय का सदुपयोग न होने से अन्ततः पछतावा, खाली हाथ मसलना पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्त अथवा नियम राष्ट्र या मानव के परिप्रेक्ष्य में समीचीन है कि प्रत्येक उपर जाने वाले को पुनश्च नीचे ही आना पड़ता है तो क्यों न शनैः शनैः उन्नति की उर्ध्वाधर मुखी की दीर्घकालीक अवधि के पश्चात ही वापस अन्तिम समय में अन्तिम पड़ाव पर पहुंचे सदैव तत्क्षण सत्यता को स्मरणित रखने वाले मानव या राष्ट्र जीवन्त पहचान स्थापित करने में सफल होंगे। विवाह, संघर्ष, युद्ध सम्बन्धित अस्त्र–शस्त्र जघन्य विनाशक हथियार से रक्षा, सुरक्षा, संरक्षा की कल्पना एक मात्र दिवास्वप्न है शान्ति, समुत्थान प्रेम सौहार्द, सम्भाव समरसता के समन्वित सम्प्रेषण से सम्भव है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त अथवा नियमों को प्रेम द्वारा ही परिवर्तित किया जा सकता है क्योंकि प्रेम ही नीचे से उपर की तरफ बहता है। वास्तविक व सच्चा (सत्य) प्रेम सदैव गुमनाम समर्पण से संयुक्त होता है। प्रेम में गिरने से बचकाने, उठने पर प्रौढ़, प्रेम से उठने पर प्रेम रिश्ता नहीं बनता, वह चेतना की दिशा बन जाता है।[4] कभी ऐतिहासिक दृष्टि से दक्षिण एशियाई क्षेत्र युद्ध, जय–पराजय से परहेज विश्व शान्ति का जगाने का अलख जगाने के लिए प्रसिद्धि मिली थी किन्तु आज दक्षिण एशियाई एवं पश्चिमी एशियाई क्षेत्र विश्व के सर्वाधिक अशान्त एवं तृतीय विश्व युद्ध प्रणेता के रूप में जाने जाएंगे। एक–दूसरे से कम न आँकने की महारत हासिल एवं एकाधिपत्य स्थापित करने की लिप्सा में आंकंठ डूबते जा रहे है। शक्ति द्वारा ही शान्ति को स्थापित करना, सौहार्द–प्रेम से दिल जीतना सम्भव है। सर्वोच्च शक्तिशाली राष्ट्र को स्वार्थ राष्ट्रीय लाभ से उपर उठकर वसुधैव कुटुम्बकम् अर्थात विश्व एक परिवार, सभी एक ही परिवार के सदस्य है। क्षेत्र–परिक्षेत्र के विविध भगौलिक वातावरण में स्त्रातजिक व सामरिकी स्वाद भी विविध है किन्तु सभी का लक्ष्य सुख–शान्ति, अमन–चमन स्थापित करना एकमात्र है। इस हेतु एक निष्कपट केन्द्रित दृढ संकल्पित आदर्श नेतृत्व की आवश्यकता है। समकालीन विश्व में कुछ अपवाद में छोड़ दिए जाए तो वास्तविक रूप में सबसे घातक जधन्य समस्या आदर्श नेतृत्व के अभाव की है। कथनी–करनी में अन्तर, लोक–लुभावनी, वाकपटुता में पारंगत है। अस्तु स्वलाभ में नित–नूतन चुनौतियाँ प्रस्तुत कर आयात–निर्यात टैक्स इत्यादि में बृद्धि कर जनमानस को अवसाद से ग्रसित करते हैं जिससे हिंसा को बढ़ावा मिलता है। विज्ञान व प्रविधा भी अपनी महत्ता से प्रत्येक जनमानस को अत्यधिक व्यस्त कर दिया है। एकल या केन्द्रित परिवार में एक दूसरे सदस्य से कुछ बार्ता/संवाद न करने में सप्ताह माह बीत जाते हैं। अतीव आवश्यकता या विशेष विषम स्थिति परिस्थिति में ही संक्षेप में ही वार्ता करते हैं। आपूर्ति न होने पर ऊँची आवाज में गरजते–बरसते है। यही स्थित विश्व राष्ट्र की है जिससे समस्याएं जटिल दीर्घकालीक समाधान असम्भावी हो जाता है। परिवार के शैशव, वयस्क भविष्य के अभिभावक है उन्हें नेतृत्व, देखभाल दोनों की आवश्यकता है किन्तु वह वंचित है विज्ञान प्रविधा उनके अभिभावक व संकल्प है अपने अभिभावक एक मात्र विकल्प है। पारिवारिक, सामाजिक राष्ट्रीय विकृतियां सम्भावी है और समाधान बारूद में ढुढते हैं। एक आदर्श नेतृत्व शोमी दास को मेवो कॉलेज, द लॉरेंस स्कूल, द दून स्कूल में वरिष्ठ शिक्षक/ (हेडमास्टर) तथा ओक्रीज इन्टरनेशनल स्कूल की सफल स्थापना का गौरव प्राप्त करने के मूल में भावी भविष्य के शिक्षार्थी को सम्यक आदर्श नागरिक निर्माण के साथ 20 सदस्य ने शिक्षार्थियों को कुशल दक्ष बनाने के लिए नौ वाल्स स्कूल की स्थापना की किन्तु आज विज्ञान–प्रविधा के विकृत परिवार

समाज राष्ट्र में सम्भव नहीं है। विकसित राष्ट्र अमेरिका की पहल पर 13–14 फरवरी वर्ष 2019 ई0 को पोलैण्ड की राजधानी वॉरसा में पश्चिम एशिया सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में स्पष्ट हुआ कि खाड़ी के राष्ट्र इजराइल के साथ सम्बन्ध बेहतर बना रहे है। सऊदी अरब, यू0ए0ई0 ओमान के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में उपस्थित थे। 13 अगस्त वर्ष 2020 ई0 को अमेरिकी मध्यस्थता में 'अब्राहमिक' समझौते की घोषणा के कुछ समय पश्चात इजराइल–यू0ए0ई0 के साथ बहरीन को सम्मिलित कर लिया गया। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जावेद ने 48 वर्ष पुराने 'इजराइल बहिष्कार कानून' को समाप्त की घोषणा पर किसी की आपत्ति नहीं नहीं हुई। स्पष्टतः कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के मामले में नहीं पड़ना चाहता है जब तक कि उसका अपना कोई हित न हो। पश्चिमी एशिया के परिप्रेक्ष्य में यह अनिवार्य है कि फलस्तीन के अस्तित्व संरक्षार्थ कौन राष्ट्र मजबूती के साथ आयेगा जो दीर्घ समय तक उसके साथ होगा यह भी संदेहास्पद है कि फलस्तीन अपने विचारात्मक प्रवाह से कितने समय तक प्रभावित कर रोक पायेगा? यह विवादास्पद विचारणीय है। स्पष्ट है कि फलस्तीन को सहजता निवेदितापूर्ण आगे कदम बढ़ाकर विश्वासपात्र किसी एक राष्ट्र का बनना पड़ेगा जिसमें आर्थिक क्षति हो सकती है। बेफिक्र रहना होगा। सामंजस्यता एवं समरसता की संजीवनी राष्ट्रों के मध्य निहित हो इसी शुभेच्छा के साथः –

संदर्भ ग्रन्थ

1– हिन्दुस्तान – दिसम्बर 2023

2– शान्तिदूत खोजता पश्चिम एशिया : लेख गांधी राजमोहन

3– भारत डिफेंस कवच दिल्ली जून–जुलाई 2024 – जोशी प्रमोद

4– ओशो

5– विकिपीडिया

6– स्वविचार

7– एक महापुरष के अनुभव की बात :– जयदयाल गोयन्दका